(b) and (c) : The teachers and other staff in the schools of Government of N.C.T. of Delhi were never declared eligible for General Pool accommodation. However, certain allotments were made to them as their applications were forwarded by the Directorate of Education (NCT) which has been an eligible office. After considering their representation for declaring them eligible for General Pool, it was clarified in December, 1991 that the teachers and other staff in the schools would not be eligible for initial allotment (in turn as well as out of turn) as they are getting allotments from Delhi Administration Pool. However, allotments already made to them would continue to be treated as lawful allotments. They would also be entitled to any consequential benefit being an allottee of G. P. such as change, ad-hoc allotment/regularisation on retirement/ death grounds to their wards employed in eligible offices.

There is no proposal for reviewing the Policy in future.

SUSPENSION OF OFFICERS OF ALIMCO

*337. PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether some of the Senior Officers of the Artificial Limbs Manufacturing Corporation Limited of India have been placed under suspension ;

(b) whether no charges could be framed against those officials even after lapes of 7 to 8 months ;

(c) whether suspension allowance has not been raised beyond 50 per cent of their pay despite loss of time ; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) : The subsistence allowance in respect of GM (Prod.) is being raised to 75% with effect from 8-10-1993. Since ex-Managing Director, ALIMCO has retired on 30th September, 1993 the question of subsistence allowance does not arise in his case.

पूर्वोत्तर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का कार्यकरण

*338. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1993-94 के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) मुख्यालय में भवनों इत्यादि के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां, कुलपति की नियुक्ति के साथ ही विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है ।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए 1000.00 लाख रु. की राशि आवंटित की गई है ।

(ग) राज्य सरकारों से भूमि प्राप्त करने तथा उसकी घेराबंदी आदि की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही भवन का निर्माण किया जाएगा । यह प्रक्रिया जारी है ।

देश में खरीफ की फसल की उपज

*339. श्री सोम पाल :
श्री शारदा महन्ती :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में खरीफ की फसल की कुल कितनी उपज हुई ;

(ख) यह उपज इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य से कितनी कम है ; और

(ग) सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) 1993-94 से संबंधित खरीफ फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार प्रमुख खरीफ फसलों का 1993-94 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्रत्याशित उत्पादन इस प्रकार है :

(मिलियन मीट्री टन/गांठें)

फसल	लक्ष्य	प्रत्याशित उत्पादन	लक्ष्य की तुलना में प्रत्याशित उत्पादन में कमी/वृद्धि की प्रतिशतता
1	2	3	4
चावल	69.5	65.5	(—) 5.8
मोटा अनाज (ग्रीष्म मक्का सहित)	30.7	27.9	(—) 9.1
दलहन	6.0	6.2	(+) 3.3
कुल खरीफ खाद्यान्न	106.2	99.6	(—) 6.2
तिलहन	11.5	11.0	(—) 4.3
गन्ना	250.0	231.0	(—) 7.6
कपास (मिलियन गांठें, प्रत्येक 170 किलोग्राम)	12.5	11.1	(—) 11.2
पटसन/मेस्ता (मिलियन गाँठें, प्रत्येक 180 कि.ग्रा.)	9.3	8.3	(—) 10.8

(ग) बिजली आपूर्ति के मामले में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है । राज्य विद्युत मंडलों/राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे किसानों को प्रतिदिन कम से कम 8 घण्टे लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें ।

देश में बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे अन्य उपाय इस प्रकार हैं :—

नए बिजलीघरों की स्थापना में तेजी लाना, लघु अवधि की परियोजनाओं का कार्यान्वयन वर्तमान बिजलीघरों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, ट्रान्समिशन तथा वितरण के दौरान होने वाले बिजली के नुकसान को कम करना मांग प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन तथा बहुलता वाले क्षेत्रों से बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में ऊर्जा अन्तरण की व्यवस्था करना आदि ।

SETTING UP OF MILK AND DAIRY UNITS

*340. **DR. YELAMANCHILI SIVAJI** : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several proposals to start milk and dairy units in various States are held up for a long time ;

(b) if so, what are the details thereof, State-wise ; and

(c) what are their proposed investment outlay and production capacity ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) :

(a) to (c) Receipt of proposals from different co-operative milk unions and federations for financing various facilities etc. and their consideration with reference to the criteria for funding stipulated by the donor agencies (World Bank/EEC) is a continuous process. Hence, there are proposals at various stages of consideration. Statewise and plant wise status of proposals, their proposed outlay and production capacity, for financing under Operation Flood is annexed as Statement.